पृथला की बेटियों को अध्यापकों के दर्शन नहीं थोक में नारा लगवा लो खट्टर सरकार से.....

पृथला से विवेक की विशेष रपट

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का मोदी-नारा हरियाणा के पानीपत से ही प्रारंभ हुआ था। अब इसके उलट, खट्टर सरकार ने राज्य की बेटियों को सरे आम उल्लू बनाना भी शुरू किया हुआ है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरीदाबाद से बीस किलोमीटर पलवल की ओर बसे पृथला गाँव की स्कूल छात्राओं ने राजमार्ग को मानव श्रंखला बना कर जाम कर दिया था। कारण था, उनके स्कूल में शिक्षकों का घोर अभाव।

पृथला स्कूल में 150 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। इतनी छात्राओं पर 16 शिक्षकों के होने की जरूरत खुद प्रशासन द्वारा स्वीकार की गई है। 16 वर्षीय छात्रा नेहा ने बताया, बीते वर्ष अगस्त माह तक स्कूल में 10 शिक्षक मौजूद थे। परंतु इसके बाद एक एक करके 6 शिक्षकों को किसी और स्कूल में भेज दिया गया। अब आलम यह है कि सिर्फ 4 शिक्षक ही सभी कक्षाओं को सारे विषय पढ़ाते हैं जबकि हाजिरी 6 शिक्षकों की लगाई जाती है। राजधानी दिल्ली की सीमा से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर खड़े पृथला गाँव में 6000 वोट हैं और इसे अब तहसील का भी दर्जा दे दिया गया है। पर ये तो वही बात कि बस कागजों में लिख दो पर सुविधा कुछ नहीं। वैसे भी इस सरकार के विजन में अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड और मुस्लिम को हिन्दू साबित करने जैसी भ्रामक कवायदें ही चल रही हैं।

ऐसे हालात में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि राज्य के स्कूलों में शिक्षा की क्या दशा होगी? पृथला में ही अंग्रेजी और इतिहास विषय के शिक्षक न होने के कारण जुगाड़ सेट करने में माहिर भारतीय परम्परा अनुसार हेडमास्टर साहब खुद ही अंग्रेजी का विषय पढ़ाने लगे। उनका स्तर क्या होगा जब बच्चों का मानना है कि जो जिस विषय का ज्ञाता हो वही पढ़ाये। अब ये बच्चे नहीं जानते कि मोदी सरकार में गृह मंत्रालय के काम का ब्यौरा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का ब्यौरा रक्षा मंत्रालय देता है तो ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक कहाँ से मिलेगा?

काजल, संजना, हिमांशी, और ईशा कक्षा नवीं की छात्रा हैं। सबने सम्मिलित रूप से बताया कि मास्टरों की कमी तो है ही, साथ ही जो मास्टर हैं उनके भी होने न होने का कोई अंतर नहीं। विज्ञान की शिक्षिका बच्चों के फेल हो जाने पर कटाक्ष करते हुए उनको ब्याह करके गोबर पाथने की सलाह देती है। ऐसे असंवेदनशील शिक्षक होंगे तो ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता ही रहेगा। कहीं न कहीं बच्चों की आत्महत्या में भी एक कारण बनते हैं ऐसे शिक्षक।

बच्चों को हतोत्साहित करने के मुद्दे पर कई अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि इस स्कूल के अध्यापक पढ़ाई में पहले से तेज तर्रार बच्चों का दाखिला कराने की मांग करते हैं ताकि इनको कम मेहनत करनी पढ़े। जब सारे बच्चे तेज होंगे तो कमजोर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? और जब सरकारों को यही सब करना है तो ये काहे बात का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ?

गांव के अनिल जो दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही कार्यरत हैं, को अफसोस था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार से तनातनी के चलते दिल्ली पुलिस की अवैध कमाई कम हो गई है पर वहीँ ये भी माना कि उन जैसों के लिए कहीं आवश्यक है शिक्षा और चिकित्सा की उचित सुविधाओं का होना। अनिल ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल को अन्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने की सिफारिश भी की।

हिमांशी और वंदना ने दसवीं कक्षा के इम्तिहान दिए हैं। गाँव के अधिकतर बच्चों की तरह इन्होंने भी पढ़ाई ट्यूशन से पूरी की। उनके अनुसार, हेडमास्टर साहब ने अपने सामर्थय भर जोर लगाया कि शिक्षकों के इस अकाल में कुछ कमी कर सकें। इसी क्रम में गाँव के सरपंच लूकरी पहलवान और हेडमास्टर ने डीईओ ऑफिस जा कर ये मुद्दा उठाया पर कानों पर जूं न रेंगने की कहावत को सही सिद्ध करते हुए डीईओ ने बात आई-गई कर दी।

पृथला गाँव के समाजसेवी धीरेन्द्र तंवर के प्रयास के चलते कुछ रोज पहले प्रशासन की ओर से एक अंग्रेजी का मास्टर भेजा गया है, पर सिर्फ इतने से तो काम नहीं बनेगा। वहीँ पड़ोस के लड़कों के स्कूल में 10 शिक्षक हैं और उन्ही को एक दिन छोड़कर बालिकाओं के स्कूल में भेजने कि कवायदें चल रही हैं। जबकि उस स्कूल में भी तय सीमा से 6 अध्यापक कम ही हैं।

अपनी बात न सुनी जाने पर छात्राओं ने एक दिन का विद्यालय बहिष्कार भी किया, पर नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला। मजबूर हो कर छात्राओं ने सबको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। आनन फानन में प्रशासन ने आश्वासन दे कर अपना पिंड छुड़ा लिया पर अभिभावकों को भी मालूम है कि ये सब खोखले वादे ही हैं। फिलहाल ग्राम सरपंच और सभी ग्रामवासी चंदा इकठ्ठा कर एक मास्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमे अभी सफलता नहीं मिली है।

देश के किसी न किसी कोने में आये दिन शिक्षा मित्र और अस्थाई नवयुवक शिक्षक धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर सरकार कोई जवाब नहीं देती, बस पुलिस की लाठियां इनकी पीठ पर तुड़वा देती है। मंदिर, नार्थ कोरिया, पाकिस्तान, देशद्रोही, और मोदी जी के गुणगान जैसे फिजूल के मुद्दों पर घंटों बहस करने वाले मीडिया संस्थानों में भी ये खबरें महत्व नहीं रखती। ये विडम्बना ही है कि जिस गाँव में बच्चे इस शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करने का वक्त सरकार के पास नहीं है।

इस बीच हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल को इसी गाँव की हरिजन चौपाल को बारात घर में बदलने के लिए रिबन काटने का वक्त मिल गया है। स्कूल में शिक्षक लगाने की राम जानें। जहाँ सरकारों से उम्मीद बेमानी दिखती है वहीँ विरोधी दलों को भी इस मुद्दे पर एकजुट होते नहीं देखा जा सकता। शायद समाज के लिए, पृथला की जागरूक बच्चियों से प्रेरणा ले कर शिक्षा जैसे मूलभूत प्रश्न पर विधायकों और सांसदों की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है।

मोदी ने मजमा लगाकर किया सड़कों का उद्घाटन, टोल टैक्स के रूप में वसूलेंगे मोटी कीमत लोगों से

नई दिल्ली (म.मो.) 28 मई को कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुये प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को बेवकूफ़ बनाने की नीयत से 27 मई को उद्घाटन सभा रखी। कहने को सभा बागपत में रखी गयी थी लेकिन यह कैराना से मात्र 25 किलोमीटर ही दूर है। हालांकि भाजपा को तब भी कैराना में मिली हार ही।

केजीपी यानी कुंडली-गाज़ियाबाद-पलवल के नाम से जाने जानी वाली इस सड़क का उद्घाटन करते हुये मोदी ने झूठ के जो गुब्बारे फ़ोड़े उनका कोई मुकाबला नहीं। सबसे पहला तो यह कि 500 दिन के रिकार्ड समय में यह 135 किलोमीटर लम्बी 6 मार्गी सड़क बनकर तैयार हो गयी।

यदि इस बात को नज़र अंदाज भी कर दें कि इस (केजीपी) सड़क व केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) सड़क बनाने की योजना गत 20 साल से चल रही है, तो भी मोदी सरकार को बने 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यदि अटल बिहारी वाजपेयी व कांग्रेसी सरकार द्वारा, इस प्रोजेक्ट पर किये गये काम को जीरो भी मान लें तो भी मोदी को पूरे 4 साल तो मिले ही हैं। फ़िर भी वे कैसे कह रहे हैं कि महज 500 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया? हुआ न सफ़ेद झूठ।

दूसरे, वे कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर 11000 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। लेकिन वे यह नहीं बताते कि ये पैसे किसने और कहां से खर्च किये हैं? इतना बड़ा खर्चा बता कर मोदी जी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे पेट्रोलियम व अन्य पदार्थों और सेवाओं पर जो भारी भरकम टैक्स वसूल रहे हैं, उसी से ऐसे प्रोजेक्ट बन पा रहे हैं। लेकिन यह भी सफ़ेद झूठ है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर एक पैसा भी नहीं लगाया।

सारा पैसा गायत्री व उसकी सहयोगी कम्पनियों ने लगाया है जो सूद समेत, लागत से कई गुणा ज़्यादा जनता से वसूलती रहेंगी। जाहिर है इस लूट में संधियों की पूरी भागीदारी रहेगी, क्योंकि बिना भागीदारी के लूट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी को भी मिलता नहीं। लूट की दरें प्रत्येक वाहन के हिसाब से रखी गयी हैं। कार के लिये 200 रुपये तो सबसे भारी ट्रक-ट्राले के लिये 1200 रुपये। ये दरें कुंडली से पलवल तक के 135 किलोमीटर के लिये हैं। बीच-बीच में 6 स्थानों पर डाईवर्ट होने वालों से कुछ कम पैसा लिया जायेगा।

अनुमान है कि इस सड़क का प्रयोग प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन करेंगे। प्रत्येक वाहन का औसत यदि 600 रुपये भी माना जाय तो 6 करोड़ रुपये रोज़ की बनेगी यह लूट कमाई। इस हिसाब से साल भर में 2190 करोड़ की लूट हो गयी। इसमें से 190 करोड़ का यदि खर्च भी घटा दें तो भी साल की लूट 2000 करोड़ बनती है। यानी साढे 5 नहीं तो 6 साल में लागत पूरी निकल जाती है। परन्तु वास्तव में यह लागत जिंदगी भर नहीं निकलने वाली। इतना ही नहीं लूट की ये दरें भी हर साल दो साल में बढती रहेंगी। सरकार चाहे भाजपा की रहे या कांग्रेस की आये, लूट का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार ने अकेले पेट्रोलियम टैक्स से ही बीते 4 वर्षों में 10 लाख करोड़ अतिरिक्त कमाया है। इस अतिरिक्त टैक्स को यदि सड़कों के निमार्ण कार्य पर लगा दिया जाता तो आम जनता को जगह-जगह टोल-टैक्स के नाम पर न लूटा जाता। मोदी का यह दावा भी खोखला है कि वे जनता से वसूले जा रहे टैक्सों से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत ढांचे) खड़े कर रहे हैं। ऐसा कोई ढांचा आज तक तो कोई कहीं नज़र आया नहीं। तमाम सड़कें व पुल, निर्माता कम्पनियों को बेच दिये गये हैं जो टोल के नाम पर जनता को लूट रहे हैं तथा आयुपर्यन्त लूटते रहेंगे।

केजीपी के साथ ही केएमपी की योजना भी बनी थी और इसका निर्माण कार्य दसियों वर्ष पहले शुरू भी हो चुका था। परन्तु सत्ताधारियों के लालच ने निर्माता कम्पनियों को इस कदर लूटा कि वे छोड़-छोड़ कर भाग गयी। अब खट्टर सरकार 44 माह से इसे पूरा करने के प्रयास में कई बार उद्घाटन की तारीख रख चुकी है। परन्तु इसकी निर्माता कम्पनी का मालिक है भाजपाई सांसद एवं जी टीवी का मालिक सुभाष चन्द्रा। उसके बस का काम तो है नहीं परन्तु किसी और को करने भी नहीं दे रहा।

27 मई को ही मोदी ने एक और छिछोरापन दिखाते हुए 150 किलोमीटर लम्बे मेरठ हाइवे के मात्र 9 किलोमीटर का उद्घाटन इस अंदाज़ में किया जैसे कोई बहुत बड़ा मोर्चा फ़तह कर लिया हो। इस हाइवे की लागत 840 करोड़ बताते हुए भी यही दर्शाया कि यह खर्चा सरकार कर रही है जबकि इसकी वसूली भी टोल टैक्स से ही होनी है। इसे देखते हुए लगता है कि भाजपा की नीति है कि काम करो या ना करो पर काम का दिखावा ज़्यादा करो और उनका ढोल भी ज़ोर-ज़ोर से पीटो।

इसी सिद्धांत पर चलते हुये स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर भी गत एक साल से, फ़रीदाबाद शहर के बीच से गुजरने वाले राजमार्ग पर आये दिन नारियल फ़ोड़ने को खड़े रहते हैं और राजमार्ग का काम है कि पूरा होने में नहीं आ रहा। इतना ही नहीं जो काम हो रहा है वह भी बहुत ही लापरवाही से, सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज करते हुए हो रहा है।

कोबरा पोस्ट ने की अपने बहुचर्चित स्टिंग 'ऑपरेशन 136' की दूसरी किस्त रिलीज

कोबरा पोस्ट ने अपने बहुचर्चित स्टिंग 'ऑपरेशन 136' की दूसरी किस्त रिलीज कर दी, इसमें दैनिक भास्कर वाला स्टिंग इसलिए रिलीज नही किया गया क्योंकि उस पर अदालत ने स्टे दे दिया है।

बहरहाल जो वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किये गए वह सभी देखने लायक हैं, पार्ट 1 ओर पार्ट 2 को यदि मिला लिया जाए तो आप पायेंगे कि देश के लगभग सभी प्रमुख मीडिया हाउस किस तरह से चंद रुपयों के लिए पत्रकारिता जैसे पवित्र माने जाने वाले पेशे की सरे बाजार इज्जत उतारने को आसानी से राजी है।

मीडिया संस्थानों से जुड़े और उनमें रुचि रखने वाले सभी मित्रों से आग्रह हैं कि बड़े मीडिया संस्थानों के मार्केटिंग मैनेजर आपकी कलम का किस तरह सौदा करते हैं एक बार जरूर देखें।

दरअसल सभी प्रतिष्ठानो के यहाँ कोबरापोस्ट के रिपोर्टर पुष्प शर्मा ने हिंदुत्व' एजेंडा चलाने के नाम पर करोड़ों रूपए के विज्ञापन का प्रलोभन दिया ओर सब के सब इस बात के लिए तैयार दिखे।

जिसे देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया समूह माना जाता हैं ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने 500 करोड़ के विज्ञापन लेकर हिंदुत्व एजेंडा चालने पर हामी भर दी। लेकिन वो अरबों रूपए कैश में लेने को तैयार नहीं हुए। जब संघ के नेता का वेश धारण किये रिपोर्टर ने जैन से कहा कि वो नकद पैसा विदेश में ले लें तो टाइम्स ग्रुप के मालिक का कहना था कि अगर वो इस नकद पैसे को अम्बानी या अडानी को दे दें तब वो किसी डील के तहत ये पैसा इन औद्योगिक घरानो से ले लेंगे।

टाइम्स ग्रुप के टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा इस स्टिंग ऑपरेशन में इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, नेटवर्क 18, स्टार इंडिया, ABP न्यूज, दैनिक जागरण, रेडियो वन, रेड एफएम, लोकमत, ABN आंध्रा ज्योति, टीवी 5, दिनामलार, बिग एफएम, के न्यूज, इंडिया वाइस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, MVTV और ओपन मैगजीन जैसे मीडिया समूह को बेनकाब किया गया हैं लेकिन इस लिस्ट में सबसे अधिक चौकाने वाला नाम है PAYTM का.....

इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में देश की अग्रणी मोबाइल बैंकिंग कंपनी पेटीएम के मालिक ने ऑन कैमेरा यह स्वीकार किया है कि पेटीएम ने PMO के आदेश पर उपभोक्ताओं का निजी डाटा सरकार को लीक किया है।

लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नही है पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा जिस तरह से इस वीडियो में आरएसएस के साथ अपने संबंधों का बढ़चढ़ कर वर्णन कर रहे है वह वाकई देखने लायक है।

पुष्प शर्मा जो आरएसएस के एजेंडे के तहत कार्य करने वाले एजेंट बने हैं उनसे अजय शेखर पूछते हैं कि "संगठन को सामने नहीं लाएंगे ? मैं तो संघ से बहुत जुड़ा हुआ हूं" इस एक वाक्य के जरिए अजय शेखर संघ से अपने जुड़ाव का खुलासा करते हैं।

आगे अजय शेखर अरुण कुमार, कृष्णा गोपाल, एस के मिश्रा और यहां तक कि शिव राज चौहान से भी अपनी नजदीकियों के बारे में बताते हैं। अजय शेखर बताते है कि उनकी संघ के इन सभी बड़े नेताओं से बातचीत है, और उनसे व्यावसायिक रिश्ते भी है, "संघ में centre में मिला हुआ हूं अरुण कुमार जी, प्रफुल केल्कर जो एडिटर मतलब मेरे कभी discussion में ये बात आई नहीं निकलकर जो बात आप बोल रहे हो मतलब मेरे हर तरह के discussion होते हैं।"

अजय शेखर बातों बातों मे यहाँ तक बोल जाते हैं कि पंचजन्य के संपादक केलकर उनके अच्छे मित्र हैं और कहते हैं कि "अरे मेरी दोस्ती तो उनसे दोस्ती का मतलब आप अगर पंचजन्य को उठाएंगे ना तो उसमें पेटीएम के एड दिखेंगे आपको।।आप देखना कभी जाके आपको दिख जाएगाज्वो उनके कहने से करे हैं हमने।"

अंडर कवर रिपोर्टर बने पुष्प शर्मा अजय से गुरुजी की वीडियो PAYTM पर अपलोड करने के लिए आग्रह करते हैं। इसपर अजय शेखर पुष्प को आश्वस्त कराते हुए कहते हैं कि "नहीं नहीं वो सब हम कर देंगे अगर RSS कहेगा क्योंकि RSS तो हमारे ब्लड में है।" आगे अजय शेखर बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं "मैं पूछूंगा करना है तो फिर उनको बताकर करेंगे हम भी तो अपने नंबर बनाएं सीधी सी बात है जब इतना कर चुके हैं तो करना ही क्या है।"

अब आप खुद समझ सकते है कि पेटीएम इतनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ गया..... कैसे ओर क्यों अप्रैल 2015 में पेटीएम ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया, जिसमें पेमेंट वॉलेट टिकटिंग के लिए स्वीकार्य था, जो मौका SBI जैसे सरकारी बैंक को सबसे पहले मिलना चाहिए था। कैसे ओर क्यों पेटीएम अपने विज्ञापनों में पीएम मोदी को ब्रांड एम्बेस्डर के तौर पर लगातार प्रस्तुत करता रहा..... कैसे ओर क्यों नोटबन्दी जैसा डिजास्टर स्ट्रोक पेटीएम के लिए जीवनदायी साबित हुआ।

क्योंकि उसे सब पहले से पता था उसकी तैयारियां पहले से ही थी , मोदी सरकार के हर मूव की पेटीएम को पहले से खबर थी। आप भले ही कुछ और न देखें लेकिन यह स्टिंग आप जरूर देखें।

- गिरीश मालवीय की विशेष रपट

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06